

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल 2026 — वैशाख 8, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026

क्रमांक 872/डी. 60/21-अ/प्रारू./छ.ग./26.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-04-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 10 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026.

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहलायेगा । **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 44 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:- **धारा 44 का संशोधन.**

"(क) यदि ऐसा आदेश, उपखण्ड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, तो कलेक्टर को होगी ।

(क-क) यदि ऐसा आदेश, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, तो आयुक्त को होगी।"

3. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) के खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात्:-

धारा 50 का संशोधन.

"(पाँच) स्वप्रेरणा से लिए गये पुनरीक्षण का निराकरण 30 दिवस एवं पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर दर्ज पुनरीक्षण का निराकरण 90 दिवस के भीतर किया जायेगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (2) के प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

धारा 59 का संशोधन.

"परंतु, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, प्रचलित औद्योगिक विकास नीति एवं अन्य विभागीय नीतियों/योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान कर सकेगी:"

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026

क्रमांक 872/डी. 60/21-अ/प्रा.ग./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2026)

**THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE
(AMENDMENT) ACT, 2026.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-seventh year of the Republic of India, as follows: -

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2026.

**Short title and
commencement.**

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For clause (a) of sub-section (2) of Section 44 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clauses shall be substituted, namely:-

**Amendment of
Section 44.**

“(a) if such order has been passed by the Sub-Divisional Officer or the Deputy-Survey Officer, to the Collector;

(a-a) if such order has been passed by the Collector or the District Survey Officer, to the Commissioner;”

3. After clause (iv) of sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely:-

**Amendment of
Section 50.**

“(v) The revision taken up suo motu shall be disposed of within 30 days, and the revision registered on an application made by a party shall be disposed of within 90 days.”

4. For the first proviso to sub-section (2) of Section 59 of the Principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:-

**Amendment of
Section 59.**

“Provided that, the State Government may by notification grant exemption from reassessment for the implementation of the prevailing Industrial Development Policy and other departmental policies/schemes:”